कार्यालय मुख्यआयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र),जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

SPEAKING ORDER/स्पीकिंग आदेश

Establishment Order No:- CCU-07/2026

(स्थापना आदेश संख्या:- सीसीयू-**07/2026)**

Dated:-As per E-signature

दिनांक :-ई-हस्ताक्षर के अनुसार

(Arising out of Following O.A.'s filed in the Hon'ble CAT Bench, Jaipur/ माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर बेंच में दायर निम्न मूल आवेदनों से उत्पन्न)

Table-1

Sr. No.	O.A No.	Name of Applicant	Designation of Applicant	Date of Order
1	2	3	4	5
1.	480/2025	Mukesh Kumar Mann	Superintendent	19.09.2025
2.	481/2025	Shiv Prakash	Superintendent	19.09.2025
3.	482/2025	Vijay Singh	Inspector	19.09.2025
4.	517/2025	Bheem Singh Meena	Inspector	07.10.2025
5.	518/2025	Amit Kumar	Superintendent	07.10.2025
6.	519/2025	Peeyush Moyal	Superintendent	07.10.2025
7.	520/2025	Jitendra Kumar Meena	Inspector	07.10.2025
8.	539/2025	Pritam Sharma	Superintendent	17.10.2025
9.	540/2025	Narendra Kumar Sharma	Superintendent	17.10.2025
10.	541/2025	Chandra Shekhar Soni	Superintendent	17.10.2025

BRIEF FACTS OF THE CASES/मामलों के संक्षिप्त तथ्य:-

The Applicants of the aforesaid OA's have prayed for issuance of directions to the Respondents to grant benefit of 4 years time-bound grade pay of Rs. 5400 in PB-2 on completion of four years' service in the grade pay of Rs. 4800 in PB-2 from due dates and not to insist upon 4 years' service as service in promoted pay scale as the same is opposed to basic policy decision

dated 29.08.2008 issued by the Respondent No. 2 (i.e. Central Board of Indirect Taxes & Customs) and law declared by Hon'ble High Court of Madras in W.P. No. 13225 of 2010 - M. Subramaniam Vs. Union of India & Others decided on 06.09.2010.

उपरोक्त मूल आवेदनों के आवेदकों ने यह प्रार्थना की है कि उन्हें चार वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण करने पर, वेतन बैंड-2 में ग्रेड पे ₹4800 में सेवा की देय तिथियों से, वेतन बैंड-2 में ₹5400 के समयबद्ध (टाइम-बाउंड) ग्रेड पे का लाभ प्रदान करने तथा चार वर्षों की सेवा को पदोन्नत वेतनमान में की गई सेवा के रूप में मानने की शर्त पर ज़ोर न दिये जाने के प्रतिवादियों को निर्देश जारी किये जायें चूँकि यह शर्त प्रतिवादी संख्या-2 (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) द्वारा दिनांक 29.08.2008 को जारी मूल नीतिगत निर्णय तथा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13225/2010-एम. सुब्रमणियम बनाम भारत संघ एवं अन्य-में दिनांक 06.09.2010 को घोषित विधि के भी प्रतिकूल है।

2. The Tribunal has disposed of the aforesaid O.A.s with a direction to the Respondents to consider and decide the representations of the Applicants, if facts of the present Applicants are similar, in light of the Order dated 06.09.2010 passed by the Hon'ble High Court of Madras in the case of M. Subramaniam Vs. Union of India & Ors. within a period of two months from the date of receipt of certified copy of orders. The Tribunal has further directed (in orders mentioned at Sl. No. 4 to 10 of table above) that in case the Respondents find the case of the Applicants similar to the one decided by the Hon'ble High Court of Madras, the benefits of the same shall be paid from the date of completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4800 /- .

अधिकरण ने उपरोक्त मूल आवेदनों का निस्तारण करते हुये प्रतिवादियों को यह निर्देश दिये है कि वे आवेदकों के अभ्यावेदनों पर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एम. सुब्रमणियम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 06.09.2010 को पारित आदेश के आलोक में विचार कर उनका निस्तारण करें और यदि वर्तमान आवेदकों के तथ्य समान हों, तो आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाये । अधिकरण ने आगे (उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 4 से 10 में उल्लिखित आदेशों में) यह भी निर्देश दिया है कि यदि प्रतिवादियों द्वारा आवेदकों के मामलों को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले के समान पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में रु.4800/- के ग्रेड पे में चार वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण होने की तिथि से संबंधित लाभ प्रदान किये जायें।

3. The details regarding dates of receiving of certified copy of the aforesaid OA's and the dates of representations of the applicants of the aforesaid OA's are as under:-

उपरोक्त मूल आवेदनों की प्रमाणित प्रातियाँ प्राप्त होने की तिथियों तथा उपरोक्त मूल आवेदनों के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों की तिथियों का विवरण निम्नानुसार है:-

Table-2

Sr. No	O.A. No.	Applicant of the O.A.	Designation	Date of Order	Date of issuance of certified copy of Order	Date of representation of the Applicant
1	2	3	4	5	6	7
1.	480/2025	Mukesh Kumar Mann	Superintendent	19.09.2025	14.11.2025	23.06.2025
2.	481/2025	Shiv Prakash	Superintendent	19.09.2025	14.11.2025	10.03.2025
3.	482/2025	Vijay Singh	Inspector	19.09.2025	14.11.2025	03.07.2025
4.	517/2025	Bheem Singh Meena	Inspector	07.10.2025	10.10.2025	18.03.2025
5.	518/2025	Amit Kumar	Superintendent	07.10.2025	10.10.2025	28.05.2025
6.	519/2025	Peeyush Moyal	Superintendent	07.10.2025	10.10.2025	06.05.2025
7.	520/2025	Jitendra Kumar Meena	Inspector	07.10.2025	09.10.2025	20.03.2025
8.	539/2025	Pritam Sharma	Superintendent	17.10.2025	27.10.2025	29.05.2025
9.	540/2025	Narendra Kumar Sharma	Superintendent	17.10.2025	27.10.2025	03.04.2025
10	541/2025	Chandra Shekhar Soni	Superintendent	17.10.2025	27.10.2025	23.04.2025

4. The representations of the applicants had already been decided by the department in terms of Board's letters F.No. A.26017/98/2008-Ad.IIA dated 21.11.2008, 11.02.2019, 16.09.2009 and letter F.No. 23011/67/2020-Ad.IIA dated 07.04.2021. Aggrieved by the same, the applicants had filed OA's detailed above. The Tribunal had directed to decide the representations in light of the order dated 06.09.2010 passed by the Hon'ble High Court of Madras in the case of M Subramaniam Vs Union of India & Ors. within a period of two months from the date of receipt of a certified copies of these orders.

आवेदकों के अभ्यावेदनों का विभाग द्वारा पहले ही बोर्ड के पत्र संख्या F.No. A.26017/98/2008-Ad.IIA दिनांक 21.11.2008, 11.02.2019, 16.09.2009 तथा पत्र संख्या F.No. 23011/67/2020-Ad.IIA दिनांक 07.04.2021 के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया जा चुका था। इससे असंतुष्ट होकर आवेदकों ने उपरोक्त विवरणानुसार मूल आवेदन दायर किये। अधिकरण ने यह निर्देश दिया कि इन आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ

प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एम. सुब्रमणियम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 06.09.2010 को पारित आदेश के आलोक में, आवेदकों के अभ्यावेदनों को निर्णित किया जाये ।

5. Since, the issue involved in the matter is related to the policy formulated by the DoPT & the Board, the matter was taken up with the Board vide this office letter even F.No. dated 08.12.2025. The Board after examination, vide letter F.No. A-23011/44/2020-Ad.IIA-Part (2) dated 19.12.2025 has directed to implement the aforementioned Orders of the Tribunal in respect of the applicants on in personam basis only, by way of issuing the speaking order provided that the cases are similar to the case covered in the Hon'ble Madras High Court order dated 06.09.2010 in W.P. No. 13225/2010 passed in M. Subramaniam case against which SLP was dismissed.

चूँकि मामले में निहित विषय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और बोर्ड द्वारा निर्मित नीति से संबंधित है, अतः प्रकरण को इस कार्यालय के पत्र फाईल सम संख्या दिनांक 08.12.2025 के द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने जांच के पश्चात, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 के पत्रांक F.No. A-23011/44/2020Ad IIA-(Pt.2) के माध्यम से निर्देश दिया कि अधिकरण के उपरोक्त आदेशों को, केवल आवेदकों के संदर्भ में, इन पर्सोनम आधार पर सकारण आदेश जारी करते हुए लागू किया जाये, बशर्ते कि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश, जो कि डब्ल्यू.पी. सं. 13225/2010- एम. सुब्रमण्यम मामले में पारित हुआ है एवं जिसके विरुद्ध दायर SLP को खारिज किया गया था, से तथ्यात्मक रूप से समान हो।

DISCUSSION AND FINDINGS/चर्चा एवं निष्कर्ष**:-**

6. In pursuance to Hon'ble CAT Jaipur Bench aforesaid Orders, the matter has been thoroughly examined and it is observed that aforesaid officers of Jaipur Zone have filed OA's before the Hon'ble Tribunal for issuance of directions to the respondents to extend the benefit of fixation in Grade Pay of Rs. 5400 /- in PB-2 upon completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4800 in PB-2.

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर पीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालना में प्रकरण की गहन जाँच की गई है तथा यह पाया गया है कि जयपुर ज़ोन के उपरोक्त अधिकारियों ने माननीय अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किये हैं, जिनमें

प्रतिवादियों को यह निर्देश दिये जाने की प्रार्थना की गई है कि वे वेतन बैंड-2 में ग्रेड पे रु.4800 में चार वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने पर, वेतन बैंड-2 में रु.5400 के ग्रेड पे में वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान करें।

7. The instructions regarding grant of Non-Functional Grade issued by the DoP&T and CBIC from time to time as well as various orders passed by the Hon'ble CAT/Courts are, briefed as under:

गैर-कार्यात्मक ग्रेड प्रदान करने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों तथा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

7.1. The 6th Central Pay Commission gave various recommendations for fixing of pay of employees of the Government of India. The recommendations accepted by the Government were notified vide GSR 622 (E) dated 29th August 2008 as Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008. As per Section II of Part-C of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, it was informed that the revised pay structure mentioned in Column (5) and (6) of this part of the Notification for the posts mentioned in Column (2) have been approved by the Government. In Section – II of the said Notification, it is laid down against Sl. No. 9, under the Head 'Department of Revenue, Ministry of Finance' that Income Tax Officers/Superintendents/Appraisers etc. (Customs & Central Excise) be placed in the Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised) in Pay Band–2 with Grade Pay of Rs. 4800/-. Further it has been mentioned that they will be placed in Revised Pay Scale of Rs. 8,000–13,500 in PB-2 with Grade Pay of Rs. 5,400/- after 4 years. Section I of Part A of the First Schedule to the Rules, provides the Revised Pay Bands and Grade Pays for posts carrying scales in Group 'A,' 'B,' 'C' & 'D' except posts for which different revised scales are notified separately. As per the same, the revised pay structure for employees in the Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised) has been rectified as Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4800/-.

छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए विभिन्न सिफारिशें दीं। सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों को दिनांक 29 अगस्त 2008 को GSR 622(E) के माध्यम से केंद्रीय सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2008, में अधिसूचित किया गया। केंद्रीय सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियमों के पार्ट- सी के भाग II के अनुसार सूचित किया गया कि अधिसूचना के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों के लिए कॉलम (5) और (6) में उल्लिखित संशोधित वेतन संरचना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया

गया है। उक्त अधिसूचना के भाग II में, क्र. सं. 9 के अंतर्गत, 'वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग' के शीर्षक के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि आयकर अधिकारी/अधीक्षक/मूल्यांकक आदि (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) को वेतनमान ₹7500–12000 (पूर्व-संशोधित) में पे बैंड–2, ग्रेड पे ₹4800/- के साथ रखा जाये। इसके अतिरिक्त उल्लेख किया गया है कि 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद उन्हें ₹8000–13500 में संशोधित वेतनमान, पे बैंड–2 के साथ ग्रेड पे ₹5400/- में रखा जायेगा। नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग A के सेक्शन I में, समूह 'A', 'B', 'C' और 'D' में वेतनमान वाले पदों के लिए संशोधित वेतनबैंड और ग्रेड पे प्रदान किये गये हैं, सिवाय उन पदों के जिनके लिए अलग से संशोधित वेतनमान अधिसूचित किया गया है। इसके अनुसार, पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500–12000 वाले कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना ₹9300–34800 के वेतनबैंड में, ग्रेड पे ₹4800/- के साथ निर्धारित की गई है।

7.2. The Ministry, vide letter under F. No. A. 26017/98/2008-Ad.IIA dated 21st November 2008, referred to Part – C, Section – II of the CCS (Revised Pay) Rules, 2008, wherein under the heading of 'Ministry of Finance, Department of Revenue' at Sl. No. 9, it is indicated that Superintendents, Appraisers, etc. (Customs and Central Excise) [who are in the pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000] shall be granted Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-2 [corresponding to pre-revised scale of Rs. 8,000-13,500], after 4 years of service. Further, in Clause (x)(e) of Para 1 of the RESOLUTION of the Department of Expenditure dated 29th August 2008 also it was indicated that "*Group-B Officers of Departments of Posts, Revenue etc. will be granted Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-2 on non-functional basis after 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4800/- in PB-2.*" The Ministry in Para 3 of aforesaid letter dated 21st November 2008, stated that the Department of Expenditure has clarified that the 4-years period is to be counted with effect from the date on which an officer is placed in the Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised).

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 नवंबर 2008 को पत्रांक F. No. A. 26017/98/2008-Ad.IIA मे केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008, भाग C, सेक्शन II का संदर्भ दिया, जिसमें 'वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग' के शीर्षक के अंतर्गत क्र. सं. 9 में यह दर्शाया गया है कि अधीक्षक, मूल्यांकक आदि (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) [जो पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500–12000 में हैं] को 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- प्रदान किया जाएगा [जो पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹8000–13500 के अनुरूप है]। इसके अतिरिक्त, व्यय विभाग संकल्प (Department of Expenditure Resolution) दिनांक 29 अगस्त 2008 के पैरा 1 की उपधारा (x)(e) में भी यह संकेत दिया गया है कि "डाक, राजस्व आदि विभागों के समूह-बी अधिकारी नियमित रूप से ग्रेड पे ₹4800/- में PB-2 में 4 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत गैर-कार्यात्मक आधार पर PB-2 में ग्रेड पे

₹5400/- प्राप्त करेंगे।" मंत्रालय ने अपने पत्रांक दिनांक 21 नवंबर 2008 के अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया कि व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने स्पष्ट किया है कि 4-वर्ष की अवधि की गणना उस तिथि से की जायेगी जिस दिन किसी अधिकारी को ₹7500-12000 (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में रखा गया हो।

7.3. Further, the Ministry vide Para 3 of letter F. No. A.26017/98/2008-Ad.IIA dated 11th February 2009, on the issue clarified that the matter has been examined in consultation with the Department of Expenditure who have clarified the matter as under:-

इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 11 फरवरी 2009 के पत्रांक F. No. A.26017/98/2008-Ad.IIA के अनुच्छेद 3 में इस विषय पर स्पष्ट किया कि मामले की जांच व्यय विभाग (Department of Expenditure) के परामर्श से की गई, जिन्होंने इस विषय पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:-

".... Non-functional upgradation to the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Pay Band PB-2 can be given on completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2 (pre-revised scale of Rs. 7500-12000) after regular promotion and not on account of financial upgradation due to the ACP."

7.4. The Hon'ble CAT, Madras Bench, vide its order dated 19th April 2010 had dismissed the O.A. No. 167/2009 seeking grant of Grade Pay of Rs. 5,400/- and the consequential benefits with effect from 01st January 2008 as per the orders of the Government of India accepting the recommendations of the 6th CPC. Being aggrieved by the dismissal of the aforesaid O.A., Shri M. Subramaniam filed W.P. No. 13225 of 2010 before the Hon'ble High Court of Judicature at Madras. The Hon'ble High Court of Judicature at Madras, vide order dated 06th September 2010, made the following observations:-

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ ने दिनांक 19 अप्रैल 2010 के अपने आदेश के माध्यम से मूल आवेदन संख्या 167/2009, जिसमें ग्रेड पे ₹5400/- और इसके अनुषंगिक लाभ 01 जनवरी 2008 से प्राप्त करने की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया था, जो कि भारत सरकार द्वारा छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6th CPC) की सिफारिशों को स्वीकार करने के आदेशों के अनुसार था। उक्त मूल आवेदन के खारिज किये जाने से असंतुष्ट होकर, श्री एम. सुब्रमण्यम ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 13225/2010 दायर की। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 06 सितंबर 2010 के अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:-

"7. We are unable to agree with this clarification given by the Under Secretary to the Government of India, since in an earlier clarification dated 21.11.2004 (correct date 21.11.2008) of the Deputy Secretary to Government of India, it was clarified as to how the 4-year period is to be counted for the purpose of granting non-functional upgradation to Group-B Officer, i.e. whether the 4-year period is to be counted with effect from the date on which the officer is placed in the pay scale of Rs. 7,500-12000 (pre-revised) or with effect from 01.01.2006, i.e. the date on which the recommendation of the 6th CPC came into force. It was clarified that the 4-year period is to be counted with effect from the date on which an officer is placed in the pay scale of Rs. 7,500-12000 (pre-revised).

8. Thus, if an officer has completed 4 years on 01.01.2006 or earlier, he will be given the non-functional upgradation with effect from 01.01.2006 and if the officer completes 4-years on a date after 01.01.2006, he will be given non-functional upgradation from such date on which he completes 4-year in the pay scale of Rs. 7,500-12,000/- (pre-revised), since the petitioner admittedly completed 4-year period in the pay scale of Rs. 7500-12000 as on 01.01.2008, he is entitled to the grade pay of Rs. 5400/-. In fact, the Government of India having accepted the recommendations of the 6th Pay Commission, issued a resolution dated 29.08.2008 granting grade pay of Rs. 5400/- to Group B officers in Pay Band-2 on non-functional basis after four years of regular service in the grade pay of Rs. 4800/- in Pay Band-2. Therefore, denial of the same benefit to the petitioner based on the clarification issued by the Under Secretary to the Government of India was contrary to the above said clarification and without amending the rules of the revised pay scale, such decision cannot be taken. Therefore, we are inclined to interfere with the order of the Tribunal.

9. Accordingly, the Writ Petition is allowed setting aside the order of the Tribunal, dated 19.4.2010 passed in O.A. No. 167 of 2009. The respondents are directed to extend the benefit of grade pay of Rs. 5,400/- to the petitioner from 01.01.2008 as per the resolution dated 29.08.2010 (correct date 29.08.2008)."

7.5. Department of Expenditure, vide Resolution No. 1/1/2008-IC dated 29th August 2008, has specified that the Group 'B' officers of the Department of Revenue will be granted Grade Pay of Rs. 5,400/- in Pay Band–2 on non-functional basis after 4 (four) years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in Pay Band– 2. Para 1(x)(e) of the resolution dated 29th August

2008 issued by the Department of Expenditure is reproduced below for the sake of convenience :-

व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने दिनांक 29 अगस्त 2008 के संकल्प संख्या 1/1/2008-IC के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग के समूह 'B' के अधिकारियों को PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में चार वर्ष नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात PB-2 में गैर-कार्यात्मक आधार पर ग्रेड पे ₹5400/- प्रदान किया जायेगा। सुविधा के लिए व्यय विभाग द्वारा 29 अगस्त 2008 के संकल्प का अनुच्छेद 1(x)(e) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

> "*Group 'B' officers of Department of Posts, Revenue etc. will be granted grade pay of Rs. 5400/- in PB-2 on non-functional basis after 4 years of regular service in the grade of Rs. 4800/- in PB-2.*"

7.6. Further, on receipt of some other references from field formations of CBEC (now CBIC) as to whether the officers who have got the pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000 by virtue of financial upgradation under ACP will also be entitled to the benefit of further non-functional upgradation on completion of 4 years in the prescribed Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised) in terms of the recommendations of the 6th CPC as accepted by the Government, the matter was again examined at length in consultation with the Department of Expenditure and it was clarified as under :-

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (अब केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के क्षेत्रीय गठन से यह संदर्भ प्राप्त होने पर कि क्या वे अधिकारी जिन्होंने ACP के तहत वित्तीय उन्नयन के कारण पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500-12000 प्राप्त किया है, उन्हें भी निर्धारित वेतनमान ₹7500-12000 (पूर्व-संशोधित) में 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा स्वीकार की गई छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6th CPC) की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त गैर-कार्यात्मक उन्नयन का लाभ मिलेगा या नहीं, इस विषय को पुनः व्यय विभाग (Department of Expenditure) के परामर्श से विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया और निम्नानुसार स्पष्ट किया गया:-

> *".....Non-functional upgradation to the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Pay Band PB-2 can be given on completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2 (pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000) after regular promotion and not on account of financial upgradation due to ACP."*

Accordingly, a clarification to this effect was issued vide Board's letter F. No. A.26017/98/2008-Ad.II.A dated 11.02.2009.

इसके अनुरूप, इस संदर्भ में स्पष्टीकरण बोर्ड के पत्रांक F. No. A.26017/98/2008-Ad.II.A दिनांक 11.02.2009 के माध्यम से जारी किया गया।

7.7. In view of the above facts, the order of the Hon'ble High Court of Judicature at Madras was examined in light of clarification dated 11.02.2009 on grant of Non-functional grade in the Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-2 to Group 'B' officers in consultation with Department of Expenditure in the case of Shri M. Subramaniam Vs. Union of India.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश की जांच की गई और श्री एम. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ मामले में व्यय विभाग (Department of Expenditure) के परामर्श से समूह 'B' अधिकारियों को PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- में गैर-कार्यात्मक ग्रेड प्रदान करने के संबंध में दिनांक 11.02.2009 के स्पष्टीकरण के आधार पर समीक्षा की गई।

7.8. Department of Expenditure, vide UO No. 15(23)E.III(B)/2010 dated 24.12.2010, clarified that non-functional upgradation to the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Pay Band PB-2 can be given on completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2 (pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000) after regular promotion and not on account of financial upgradation due to ACP. In the case of Shri M. Subramaniam, he was holding the post of Inspector and was granted the Grade Pay of Rs. 4,800/in PB-2 under ACP Scheme. He was not promoted to the post of Superintendent/Appraiser and as such, he had not rendered any regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/-. Therefore, he could not be extended the benefit of the Grade Pay of Rs. 5,400/- after 4 years of service in the Grade Pay of Rs. 4,800/-. DoP&T also endorsed the view of the Department of Expenditure.

व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने UO संख्या 15(23)E.III(B)/2010 दिनांक 24.12.2010 के माध्यम से स्पष्ट किया कि PB-2 वेतन बैंड में ग्रेड पे ₹5400/- में गैर-कार्यात्मक उन्नयन केवल तब दिया जा सकता है जब अधिकारी ने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- (पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500–12000) में नियमित सेवा के 4 वर्ष पूर्ण कर लिये हों, और यह नियमित पदोन्नति के आधार पर होना चाहिए, सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के आधार पर नहीं। श्री एम. सुब्रमण्यम के

मामले में, वह निरीक्षक के पद पर तैनात थे और उन्हें सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के तहत PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- प्रदान किया गया था। उन्हें अधीक्षक/मूल्यांकक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था और इसलिए उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में कोई नियमित सेवा नहीं दी थी। अतः उन्हें PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में 4 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बाद ग्रेड पे ₹5400/- का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भी व्यय विभाग के इस दृष्टिकोण को अनुमोदित किया।

7.9. Accordingly, an SLP No. 15627 of 2011 was filed before the Hon'ble Supreme Court (subsequently converted to Civil Appeal No. 8883/2011) against the Hon'ble Madras High Court's Order dated 06.09.2010 in W.P. No. 13225/2010. The Hon'ble Supreme Court, vide order dated 10.10.2017, did not see any ground to interfere with the impugned order and, accordingly, dismissed the appeal and the SLP filed by the Union of India.

अतः, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश (रिट याचिका सं. 13225/2010) के खिलाफ, भारत संघ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP संख्या 15627/2011 दायर की गई (जिसे बाद में सिविल अपील संख्या 8883/2011 में परिवर्तित किया गया)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2017 के अपने आदेश में विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और तदनुसार अपील और भारत संघ द्वारा दायर SLP को खारिज कर दिया।

7.10. Thereafter, a Review Petition (Civil) No. 2512 of 2018 in Civil Appeal No. 8883 of 2011 was also filed by the Union of India before the Hon'ble Supreme Court, which was also dismissed vide order dated 23.08.2018, on the ground of delay as well as on merits.

इसके पश्चात, भारत संघ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 8883/2011 में समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 2512/2018 भी दायर की, जिसे 23.08.2018 के आदेश के माध्यम से, विलंब और याचिका की सामग्री (merits) दोनों आधारों पर खारिज कर दिया गया।

8. Since, the issue involved in the matter is related to the policy, Board's directions regarding implementation of the aforesaid Orders of the Tribunal were sought vide letter dated 08.12.2025. The Board after examination, vide letter F. No. A 23011/44/2020 Ad IIA-(Pt.2) dated 19.12.2025, has directed to implement the aforesaid Orders of the Tribunal in respect of the individual applicants on in personam basis only, by way of issuing the speaking order provided that the case is similar to the case covered in the

Hon'ble Madras High Court order dated 06.09.2010 in W.P. No 13225/2010 passed in M. Subramaniam case against which SLP was dismissed.

चूँकि, इस प्रकरण में सम्मिलित विषय नीति से संबंधित है, अतः अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में बोर्ड के निर्देश पत्र दिनांक 08.12.2025 के माध्यम से प्राप्त किये गये। बोर्ड द्वारा जाँच के पश्चात, पत्र संख्या F. No. A-23011/44/2020-Ad.IIA (भाग-2) दिनांक 19.12.2025 के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अधिकरण के उपरोक्त आदेशों को केवल इन पर्सोनम (व्यक्तिगत) आधार पर, अर्थात् केवल संबंधित व्यक्तिगत आवेदकों के संबंध में, कारणयुक्त (स्पीकिंग) आदेश जारी करते हुये लागू किया जाये, बशर्ते कि प्रकरण के तथ्य माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13225/2010 में एम. सुब्रमणियम प्रकरण में दिनांक 06.09.2010 को पारित आदेश से आच्छादित मामले के समान हों, जिसके विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) निरस्त की जा चुकी है।

9. While examining the case, it is observed, on the basis of facts mentioned in the aforesaid Order dated 06.09.2010 of the Hon'ble Madras High Court, that Shri M. Subramaniam joined service as Inspector of Central Excise on 16.01.1992. The benefit of first financial up-gradation was granted to the applicant with effect from 01.01.2004 in the pay scale of Rs. 7500-250-12000 (revised as grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 in 6th CPC and further revised as Level-8 Rs. 47600- 151100 in 7th CPC) vide order dated 11.08.2004 on the basis of the ACP Scheme. He was drawing the pay scale of Rs. 7500-250-12000 being the pay scale of Superintendent of Central Excise. Shri M Subramaniam filed O.A. No. 167/2009 in the Hon'ble CAT, Madras Bench. The Tribunal rejected the same vide Order dated 19.04.2010.

मामले की जांच करते समय, यह देखा गया कि, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर, श्री एम. सुब्रमण्यम ने 16.01.1992 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में निरीक्षक के रूप में सेवा में प्रवेश किया। पहले वित्तीय उन्नयन का लाभ याचिकाकर्ता को ACP योजना के आधार पर दिनांक 11.08.2004 के आदेश के माध्यम से 01.01.2004 से वेतनमान रु.7500-250-12000 (छठे केंद्रीय वेतन आयोग में PB-2 में ग्रेड पे रु.4800/- के रूप में संशोधित और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में स्तर-8 रु.47600-151100 में पुनः संशोधित) में प्रदान किया गया। वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक के वेतनमान रु.7500-250-12000 में वेतन प्राप्त कर रहे थे। श्री एम. सुब्रमण्यम ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ में मूल आवेदन संख्या

167/2009 दायर की, जिसे अधिकरण ने दिनांक 19.04.2010 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

9.1 Against the Order of the Tribunal, Shri Subramaniam filed Writ Petition No. 13225/2010 before the Hon'ble High Court of Madras. The Hon'ble Court vide Order dated 06.09.2010 allowed the Writ Petition filed by the applicant and set aside the order of the Hon'ble CAT, Madras Bench dated 19.04.2010 passed in the O.A. No. 167/2009. The Hon'ble High Court ordered to extend the benefit of Grade Pay of Rs 5400/- to the petitioner from 01.01.2008 as per the Resolution dated 29.08.2010 (correct date 29.08.2008). Further, the Civil Appeal No 8883/2011 and Review Petition filed by UOI against the said order w also dismissed by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated 10.10.2017.

अधिकरण के आदेश के विरुद्ध, श्री सुब्रमण्यम ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13225/2010 दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.09.2010 के अपने आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और मूल आवेदन संख्या 167/2009 में दिनांक 19.04.2010 के माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 29.08.2008 के संकल्प के अनुसार 01.01.2008 से ग्रेड पे ₹5400/- का लाभ दिया जाये। इसके अतिरिक्त, भारत संघ द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ दायर सिविल अपील संख्या 8883/2011 और समीक्षा याचिका को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

10. The facts of the case in respect of applicants have been examined. On the basis of the records of the Department, the service particulars in respect of them are as under:-

आवेदकों के संबंध में मामले के तथ्य जांचे गये हैं। विभाग के अभिलेखों के आधार पर, उनके सेवा विवरण निम्नानुसार हैं:-

Table-3

S. No.	**Name of the Officer & Date of Birth (S/Shri)**	**Designation**	**Date of joining in the Department as Inspector in Grade Pay of Rs. 4600/- in PB-2 (Revised as Level-7 in pay matrix Rs. 44900-142400)**	**Date of grant of grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 (revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100) by way of MACP Scheme (1st Financial Upgradation)**	**Due date of grant of Non-Functional Upgradation to the grade pay of Rs. 5400 in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800) counting 4 years from the date of grant of GP of Rs. 4800 in PB-2 by way of MACP Scheme**
1	2	3	4	5	6
01.	Mukesh Kumar Mann (03.02.1979)	Superintendent	20.06.2011	20.06.2021	20.06.2025
02.	Shiv Prakash (07.02.1987)	Superintendent	30.12.2010	30.12.2020	30.12.2024
03.	Vijay Singh (01.07.1985)	Inspector	06.05.2011	06.05.2021	06.05.2025
04.	Bheem Singh Meena (06.08.1984)	Inspector	28.01.2011	28.01.2021	28.01.2025
05.	Amit Kumar (16.01.1981)	Superintendent	05.05.2011	05.05.2021	05.05.2025
06.	Peeyush Moyal (24.03.1984)	Superintendent	05.05.2011	05.05.2021	05.05.2025
07.	Jitendra Kumar Meena (21.08.1985)	Inspector	17.02.2011	17.02.2021	17.02.2025
08.	Pritam Sharma (12.07.1982)	Superintendent	30.11.2010	30.11.2020	30.11.2024
09.	Narendra Kumar Sharma (27.07.1978)	Superintendent	12.01.2011	12.01.2021	12.01.2025
10.	Chandra Shekhar Soni (03.12.1979)	Superintendent	15.04.2011	15.04.2021	15.04.2025

On examination, it is found that the applicants of the aforesaid O.A.'s had been granted 1st financial upgradation under MACPS to the Level-8 in the pay matrix Rs. 47600- 151100 (pre-revised grade pay of Rs. 4800/-in PB-2 in 6th CPC) w.e.f. from the date mentioned in column no. 5 against their names in Table-3 above. Now, they are seeking the benefit of non-functional grade pay of Rs 5400/- in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800) on completion of 4 years' service in the grade pay of Rs. 4800/- in terms of judgement dated 06.09.2010 of the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 13225/2010 in the case of M. Subramaniam.

जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त वर्णित मूल आवेदनों में याचिकाकर्ताओं को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) योजना के तहत पहला वित्तीय उन्नयन वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 रु.47600–151100 में (छठे केंद्रीय वेतन आयोग में PB-2 में ग्रेड पे रु.4800/- के रूप में) उपरोक्त तालिका-3 के कॉलम संख्या 5 में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से प्रदान किया गया। अब, वे PB-2 में ग्रेड पे रु. 5,400/- (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 रु.53100–167800) का लाभ चाहते हैं, जब उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे रु.4800/- में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, जैसा कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.09.2010 के रिट याचिका संख्या 13225/2010, एम. सुब्रमण्यम मामले में अपने निर्णय में निर्देशित किया है।

As per the Hon'ble Court's Order dated 06.09.2010 (supra), Shri M. Subramaniam was granted the pay scale of Rs. 7500-12000 (revised as Grade Pay of Rs. 4800/- in PB-2 in 6th CPC) under ACP Scheme on 01.01.2004 and sought benefits of grade pay of Rs 5400/- w.e.f. 01.01.2008 i.e. on completion of 4 years service in the grade pay of Rs 4800/-in PB-2 granted by virtue of ACP Scheme. The "Modified Assured Career Progression Scheme" (MACPs) for the Central Government Civilian Employees has been issued in supersession of previous "Assured Career Progression Scheme" (ACP). Thus, the issue of Shri M. Subramaniam and aforesaid officers of Jaipur Zone is identical to each other.

माननीय न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 (सुप्रा) के आदेश के अनुसार, श्री एम. सुब्रमण्यम को सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के तहत 01.01.2004 से वेतनमान 7500-12000 प्रदान किया गया और उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 01.01.2008 से ग्रेड पे ₹5400/- का लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया। केंद्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए 'संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना' (Modified Assured Career Progression Scheme – MACPS) को पूर्ववर्ती 'सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना' (ACP) के स्थान पर जारी किया गया है। अतः, श्री एम. सुब्रमण्यम और जयपुर परिक्षेत्र के उपरोक्त वर्णित अधिकारियों का मामला परस्पर समान है।

11. In view of above, applying the ratio of the Order dated 06.09.2010 of the Hon'ble Madras High Court in W.P. No. 13225/2010 in M. Subramaniam case, it is observed that the aforesaid officers as mentioned in the table in para 10, who are also the applicant of aforesaid O.A.'s, are entitled to Non Functional Upgradation to the grade pay of Rs. 5400/- in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800 in 7th CPC) on

completion of 4 years service in the grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 in 6th CPC (revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100 in 7th CPC).

उपरोक्त के दृष्टिगत, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश (रिट याचिका सं. 13225/2010, एम. सुब्रमण्यम मामले) के तात्त्विक अनुप्रयोग के आधार पर, यह पाया गया कि पैरा 10 में वर्णित तालिका में नामित अधिकारी, जो कि उपरोक्त मूल आवेदनों में आवेदक भी है, PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-9 ₹53100-167800 में संशोधित) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन के हकदार हैं, जब उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 ₹47,600-1,51,100 में संशोधित) में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

12. Accordingly, the officers named at Sr. No. 01 to 10 in the table in para 10 above, are granted Non Functional Upgradation to the Grade Pay of Rs. 5400/- in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800 in 7th CPC) on completion of 4 years of continuous service in the Grade Pay of Rs. 4800/- in PB-2 (revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100 in 7th CPC), from the date shown against their names in Column No. 6 of the aforesaid table. The representations of all of the officers are disposed of accordingly.

अतः, उक्त पैरा 10 में वर्णित तालिका में क्रम संख्या 01 से 10 तक के अधिकारियों, को PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/-(सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 ₹47,600–1,51,100 में संशोधित) में 4 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करने पर, उपरोक्त तालिका में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 6 में दर्शायी गई तिथि से, PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 ₹53,100–1,67,800) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जाता है। उक्त सभी अधिकारियों के अभ्यावेदनों का इस निर्णय के अनुसार निपटान किया जाता हैं।

This issues with the approval of the Competent Authority.
यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी किया जाता है।

Digitally signed by
NISHTHA SHARMA
Date: 05-02-2026
11:08:21

(Nishtha Sharma/निष्ठा शर्मा)

Joint Commissioner/संयुक्त आयुक्त

F No.:- GCCO/II/26/18/2025-ADMN Date:-As per E-sign

फा.सं.- GCCO/II/26/18/2025-ADMN दिनांक:-ई-हस्ताक्षर के अनुसार

Copy for information and necessary action to:-
सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित:-

1. Officers Concerned./ संबंधित अधिकारी |
2. The Pr. Commissioner/Commissioner, CGST Udaipur/Jodhpur/ Alwar/Audit Jaipur/Audit Jodhpur/Customs (Pre.) Jodhpur.
   प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. उदयपुर/जोधपुर/अलवर/अंकेक्षण जयपुर/ अंकेक्षण जोधपुर/सीमा शुल्क (निवारक) जोधपुर |
3. The Under Secretary (Ad.IIA). Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi with reference to letter F. No. A. 23011/44/2020 Ad IIA-(Pt.2) dated 19.12.2025 for information.
   उप सचिव (Ad.IIA), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली, को पत्र फा.सं. A.23011/44/2020 Ad IIA-(Pt.2) दिनांक 19.12.2025 के संदर्भ में, सूचनार्थ |
4. The PAO, CGST & Customs, Jaipur./वेतन एवं लेखाधिकारी, जयपुर |
5. The CAO /AO (DDO), CGST Udaipur/Jodhpur/Alwar/Audit Jaipur/Audit Jodhpur/Customs (Pre.) Jodhpur.
   मुख्य लेखाधिकारी/ प्र. अधिकारी (डी.डी.ओ.) सी.जी.एस.टी. उदयपुर/जोधपुर/अलवर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/सीमा शुल्क (निवारक) जोधपुर |
6. Service Book / Guard file / Notice Board.
   सेवा पुस्तिका/गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड |
7. Webmaster for uploading a copy of the order on Zonal Website.
   क्षेत्रीय वेबसाइट पर आदेश की प्रति अपलोड करने के लिए वेबमास्टर से अनुरोध है।